फैसला सुरक्षित रखा

उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

2019 की विशेष अपील सं 149

चंद्र प्रकाश .....अपीलकर्ता

बनाम

उत्तराखंड राज्य और अन्य .....प्रतिवादी

श्री हर्षवीर प्रकाश शर्मा, अधिवक्ता, अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री संजय भट्ट के लिए संक्षेपण धारक।
श्री एस.एस. चौधरी, ब्रीफ होल्डर, उत्तराखंड राज्य के लिए।
श्री बी.डी. कांडपाल, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के लिए स्थायी अधिवक्ता।

फैसला सुरक्षित रखा गया:25.03.2019
निर्णय दिया गया:03.04.2019

संदर्भित मामलों की कालानुक्रमिक सूची:

1. 2017 (2) आर. एल. डब्ल्यू. 1545 (राज)
2. (1998) 9 एस. सी. सी. 128
3. 2010 की विशेष अपील सं. 76 दिनांक 8.6.2010 (उत्तराखंड उच्च न्यायालय)
4. 2010 की विशेष अपील सं 79 दिनांक (उत्तराखंड उच्च न्यायालय)
5. (2002) 4 एस. सी. सी. 638
6. ए.आई.आर. 1966 एस.सी. 334
7. ए. आई. आर 1962 एस. सी. 1210
8. ए. आई. आर 1973 एस. सी. 964
9. (1977) 4 एससीसी 145
10. ए.आई.आर. 1962 एस.सी. 1183
11. (1974) 3 एस.सी.सी. 220
12. (1976) 1 एस. सी. सी. 671
13. (1977) 1 एस.सी.सी. 486
14. (1998) 9 एस. सी. सी. 412
15. 1848 (2) एक्स. 654
16. (1837) 6 ए. & ई. 469
17. (2001) 2 एस.सी.सी. 41
18. 1938 ए. सी. 287
19. 1975 Q.B. 654
20. (1977) एसी 890
21. 1939 59 C.L.R. 641
22. 1956 (3) सभी ई.आर. 905)

23. (2017) 1 एससीसी 487
24. (2004) 8 एस.सी.सी. 229
25. 1989 पूरक (1) एस.सी.सी. 487
26. संस्करण 89 टैक्समैन, 287 (बम. H.C. DB)
27. [1994] 206 आई.टी.आर. 727 (बम)
28. [1994] 209 आई.टी.आर. 277 (बम)
29. (1979) 4 एससीसी 429)
30. (2008) 14 एससीसी 283
31. ए. आई. आर 1982 एस. सी 1302
32. (1960) 3 एस.सी.आर. 578
33. (1992) 1 एस.सी.सी. 489
34. (1999) 7 एससीसी 298
35. (2004) 4 एससीसी 714
36. (1985) 3 एससीसी 169
37. 1989 सप.(2) एस.सी.सी. 364
38. (2003) 7 एस.सी.सी. 546
39. (1995) 6 एससीसी 749
40. (1994) 4 एससीसी 448
41. 1995 सप.(2) एससीसी 731

कोरमः **माननीय रमेश रंगनाथन, C.J.**
माननीय N.S. धनिक, जे।

रमेश रंगनाथन, C.J.

यह अपील, रिट याचिका (एस/एस) संख्या 387/2019 दिनांक 6-3-2019 में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर की गई है। अपीलकर्ता ने यहां उक्त रिट याचिका दायर कर उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कोटा के तहत अंग्रेजी में व्याख्याता के पद पर चयन के लिए याचिकाकर्ता के दावे पर विचार करने का आदेश देने और उसे शेष चयन प्रक्रिया, यानी जो दस्तावेजों का सत्यापन और साक्षात्कार दिनांक २८-२-२०१९ से आयोजित होने वाला है, में भाग लेने की अनुमति देने की मांग की थी और उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को परमादेश देते हुए एक परमादेश पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें याचिकाकर्ता को अपने आरक्षण की श्रेणी के संबंध में आवेदन पत्र में आवश्यक सुधार करने की अनुमति

दी जाए, या उसके द्वारा अभ्यावेदन के आधार पर ऐसा सुधार करने की अनुमति दी जाए।

2. तथ्य, सीमित सीमा तक आवश्यक हैं कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा उत्तराखंड राज्य में विभिन्न सरकारी अंतर-महाविद्यालयों में अंग्रेजी में व्याख्याता के पद के लिए आवेदन आमंत्रित करने के साथ-साथ ०४-०९-२०१८ पर एक विज्ञापन जारी किया गया था। याचिकाकर्ता, निश्चित रूप से, अनुसूचित जाति का सदस्य है और उसने आवेदन पत्र के साथ अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शुल्क 60/- का भुगतान किया। आवेदन पत्र में इस सवाल के जवाब में कि क्या वह आरक्षण श्रेणी/उप श्रेणी के लाभ का दावा करना चाहते हैं, याचिकाकर्ता ने नकारात्मक में जवाब दिया। याचिकाकर्ता को जारी किए गए प्रवेश पत्र में उनकी श्रेणी को "अनारक्षित" के रूप में दर्ज किया गया था। प्रवेश पत्र की प्राप्ति पर, याचिकाकर्ता ने २४-१२-२०१८ को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया, जिसमें संबंधित अधिकारियों को सूचित किया गया कि उसने गलत तरीके से कॉलम का उत्तर दिया था, कि क्या वह आरक्षण के लाभ का दावा करना चाहता था, नकारात्मक में; और उसकी गलती को माफ किया जाए, और उसे आवेदन पत्र में त्रुटि को ठीक करने की अनुमति दी जाए। यद्यपि, तथ्य यह है कि आयोग ने उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया। आगामी प्रारंभिक परीक्षा में, याचिकाकर्ता ने 111 अंक प्राप्त किए, जो अनुसूचित जाति श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 110.5 के कट-ऑफ अंकों से अधिक है।

3. इस आधार पर कि उन्हें अवैध रूप से सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में माना गया था, और गलती से साक्षात्कार में भाग लेने के लिए अयोग्य ठहराया गया था, याचिकाकर्ता ने इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का हवाला देते हुए कहा कि, चूंकि वह अनुसूचित जातियों के सदस्य थे, इसलिए आवेदन पत्र में उनके द्वारा की गई गलती के परिणामस्वरूप उन्हें अनुसूचित जातियों के पक्ष में आरक्षित पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के उनके अधिकार से वंचित नहीं किया जाना चाहिए।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष, अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने एस्टोपेल के सिद्धांत पर भरोसा करते हुए तर्क दिया कि, हो सकता है कि उसने यह कहते हुए आवेदन पत्र भरने में गलती की हो कि वह आरक्षण के लाभ का दावा करने का इच्छुक नहीं है, अधिकारियों ने अनुसूचित जाति के आवेदकों के लिए निर्धारित कम शुल्क को स्वीकार करके भी गलती की थी, और इसलिए, उन्होंने याचिकाकर्ता के इस तर्क को चुपचाप स्वीकार कर लिया था कि वह अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार था। अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने नीतू हर्ष1 मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले पर भरोसा करते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश के समक्ष माफी के सिद्धांत पर भी भरोसा किया।

5. अपील के तहत आदेश में, विद्वान एकल न्यायाधीश ने पाया कि विज्ञापन के खंड ५(खंड ६ होना चाहिए था) में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि नाम, पात्रता, आरक्षण, शिक्षण, विषय जिसके लिए आवेदन किया गया है, आयु, आवेदन पत्र में बनाये गये परीक्षा केन्द्र आदि से संबंधित सभी प्रविष्टियों में बाद में संशोधन नहीं किया जा सकेगा; उम्मीदवारों द्वारा अनुरोध किए जाने पर भी ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जा सकेगी; आयोग दिनांक ४-९-२०१८ के विज्ञापन में निर्धारित चयन के निर्दिष्ट मानदंडों का पालन करने के लिए बाध्य था; विज्ञापित पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को विज्ञापन के संदर्भ में विभिन्न विवरण प्रदान करते समय सतर्क और सजग रहना चाहिए; विज्ञापन ने स्वयं यह प्रतिबंध लगा दिया कि ऑनलाइन जमा किए गए आवेदन पत्र में विभिन्न शीर्षकों से संबंधित कोई भी बदलाव करने के लिए किसी भी प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जाएगा; और इसलिए याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर कार्रवाई करने से इनकार करने को वैधानिक प्रावधानों के तहत किसी भी अधिकार का उल्लंघन नहीं कहा जा सकता है। इसके बाद, विद्वान एकल न्यायाधीश ने कहा कि परमादेश की प्रकृति में एक निर्देश केवल तभी जारी किया जा सकता है जब क़ानून, या क्षेत्र को नियंत्रित करने वाला कानून, सुधार की मांग के लिए प्रस्तुत किए जा रहे एक अभ्यावेदन पर विचार करता है, या जहां किसी वैधानिक अधिकार के प्रवर्तन पर विचार

करने वाले प्राधिकारियों की ओर से स्पष्ट निष्क्रियता होती है; और प्रतिनिधित्व पर विचार करने का निर्देश केवल असाधारण परिस्थितियों में ही पारित किया जा सकता है, वह भी तब जहां कानून ऐसे प्रतिनिधित्व के लिए, या वैधानिक अधिकारों को लागू करने के लिए प्रदान करता है; और, ऐसी किसी बाध्यता के अभाव में, अनुरोध, कि अभ्यावेदन पर विचार किया जाए, स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

6. क्षमा के सिद्धांत और राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले के संबंध में, जिस पर याचिकाकर्ता ने भरोसा जताया था, विद्वान एकल न्यायाधीश ने माना कि उक्त सिद्धांत चयन की प्रक्रिया पर लागू नहीं होगा, खासकर तब जब इससे चयन प्रक्रिया में व्यवधान उत्पन्न हो। इस प्रकार दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया। इससे व्यथित होकर, वर्तमान अपील दायर की गई।

7. अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील डॉ. हर्षवीर प्रकाश शर्मा का कहना है कि लोक सेवा आयोग ने याचिकाकर्ता के आवेदन शुल्क ६०/- रुपये को स्वीकार कर लिया है, जो केवल अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों पर लागू होता है, स्वयं यह दिखाता है कि उन्होंने याचिकाकर्ता की ओर से यह घोषणा करने में हुई त्रुटि को माफ कर दिया था कि वह आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहता था; उत्तरदाताओं को उसका आवेदन पत्र इस आधार पर प्राप्त हुआ था कि वह आरक्षण के लाभ का दावा कर रहा था, और अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित कोटा में पदों पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा रहा था; आवेदन प्राप्त होने और उस पर कार्रवाई करने के बाद, लोक सेवा आयोग उसे एक अनारक्षित उम्मीदवार के रूप में नहीं मान सकता था, क्योंकि उसका आवेदन अपर्याप्त आवेदन शुल्क के भुगतान के आधार पर खारिज नहीं किया गया था; राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने, कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियों में, माना कि क्षमा के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता है, और समाज के कमजोर वर्गों की ओर से हुई त्रुटि को माफ कर दिया जाना चाहिए; तथा राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के उक्त निर्णय के आलोक में याचिकाकर्ता का आवेदन पुनः प्राप्त कर कार्यवाही की जाये।

8. विद्वान अधिवक्ता हमारा ध्यान राजस्थान उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले के उस हिस्से की ओर भी आकर्षित करेंगे जिसमें सीमा कुमारी शर्मा[2] के फैसले का संदर्भ दिया गया है, यह प्रस्तुत करने के लिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था, कमोबेश ऐसी ही परिस्थितियों में, जो वर्तमान मामले में विचार के लिए उत्पन्न होती हैं, कि आवेदन प्राप्त किया जाये। वह यह प्रस्तुत करने के लिए दिनांक ४-९-२०१८ के विज्ञापन के खंड १९ पर भी भरोसा करेगा कि, इसके संदर्भ में भी, एडमिट कार्ड जारी करना निर्णायक नहीं है, और इसलिए यह स्पष्ट है कि एडमिट कार्ड प्रकृति में अनंतिम है; और याचिकाकर्ता द्वारा पहले की गई त्रुटि को हमेशा सुधारा जा सकता है।

9. दूसरी ओर, लोक सेवा आयोग के विद्वान स्थायी अधिवक्ता श्री बी.डी. कांडपाल का कहना था कि किसी विशेष उम्मीदवार के पक्ष में कोई अपवाद नहीं किया जा सकता है; लोक सेवा आयोग विज्ञापन की शर्तों से उतना ही बंधा हुआ है, जितना उसके अनुसार आवेदन करने वाले अभ्यर्थी हैं; दिनांक ४-९-२०१८ के विज्ञापन का खंड (1) यह स्पष्ट करता है कि ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज आरक्षण के लाभ का दावा करने वाले उम्मीदवारों को विशेष रूप से यह बताना आवश्यक था कि क्या वे ऐसे आरक्षण के लाभ का दावा करना चाहते हैं; उक्त विज्ञापन के खंड (६) में यह निर्धारित किया गया था कि एक बार जमा किए गए आवेदनों में उसके बाद संशोधन नहीं किया जा सकता है; विज्ञापन के अनुसार, निर्धारित शुल्क सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए १००/- रुपये और ओबीसी, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ६०/- रुपये था; लोक सेवा आयोग ने अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को ६०/-रुपये शुल्क के साथ स्वीकार कर लिया था, क्योंकि वह अनुसूचित जाति वर्ग से था; जबकि याचिकाकर्ता, निस्संदेह, अनुसूचित जाति का सदस्य था, यह उसे तय करना था कि आरक्षण के लाभ का दावा करना है या नहीं; चूंकि उन्होंने जानबूझकर आरक्षण का लाभ नहीं लेने का फैसला किया, इसलिए प्रतिवादी आयोग के पास उन्हें अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में मानने और तदनुसार प्रवेश पत्र जारी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था; इसके बाद, आवेदन पत्र भरने में उसके द्वारा पहले की गई त्रुटि को

सुधारने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता के प्रतिनिधित्व पर विचार नहीं किया जा सका, क्योंकि विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के अनुसार ऐसे किसी भी अनुरोध पर विचार करना प्रतिबंधित है; यामिनी जोशी[3] और राधा मित्तल मामले में इस उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत आवेदन में सुधार की अनुमति देने से इनकार करने में लोक सेवा आयोग की कार्रवाई को बरकरार रखा; और विद्वान एकल न्यायाधीश ने रिट याचिका को खारिज कर दिया, और आवेदन पत्र में दिए गए विवरणों में सुधार के लिए बाद में किए गए किसी भी अनुरोध पर विचार करने से इनकार करने में लोक सेवा आयोग की कार्रवाई को बरकरार रखा।

10. राहत, जो अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने २०१९ की रिट याचिका (एस/एस) संख्या ३८७ में मांगी थी, वह अनुसूचित जाति के लिए निर्धारित कोटा के तहत अंग्रेजी में व्याख्याता के पद पर चयन के लिए उनके दावे पर विचार करने के लिए लोक सेवा आयोग को निर्देश देने वाले परमादेश की रिट थी। "मैंडमस" का अर्थ है एक आदेश। यह संस्था या व्यक्ति, जिसे यह संबोधित किया जाता है, की ओर से कुछ गतिविधि की मांग में निषेध या उत्प्रेषण-लेख रिट से भिन्न है। मैंडमस एक परमादेश है जो किसी भी व्यक्ति, निगम, निचली अदालतों या सरकार को निर्देश देने के लिए जारी किया जाता है, जिसमें उसे या उन्हें उसमें निर्दिष्ट कुछ विशेष कार्य करने की अपेक्षा की जाती है जो उसके या उनके कार्यालय से संबंधित है, और एक सार्वजनिक कर्तव्य की प्रकृति में है। एक परमादेश किसी भी व्यक्ति के लिए होगा जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए किसी क़ानून या सामान्य कानून द्वारा लगाए गए कर्तव्य के अधीन है। **(एम.आर. अप्पा राव[3]).** परमादेश-पत्र का मुख्य कार्य क़ानून द्वारा निर्धारित सार्वजनिक कर्तव्य के पालन को बाध्य करना और अधीनस्थ न्यायालयों/न्यायाधिकरणों और सार्वजनिक कार्यों का प्रयोग करने वाले अधिकारियों को उनके अधिकार क्षेत्र की सीमा के भीतर रखना है। **(लेखराज सतरामदास लालवानी[0]; राय शिवेन्द्र बहादुर (डॉ)'; उमाकांत सरन डॉक्टर[3]; सिपाही सिंह')।**

11. परमादेश जारी करने के लिए अनुच्छेद 226 के तहत शक्ति का प्रयोग करने की शर्तों में से एक यह है कि न्यायालय को इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि पीड़ित व्यक्ति के पास कानूनी अधिकार है, और इस तरह के अधिकार का उल्लंघन किया गया है।आवेदक को न्यायालय को संतुष्ट करना होगा कि उसके पास उस पक्ष द्वारा कानूनी कर्तव्य के प्रदर्शन का कानूनी अधिकार है जिसके खिलाफ परमादेश मांगा गया है। जो कर्तव्य परमादेश द्वारा सौंपा जा सकता है वह संविधान, क़ानून, सामान्य कानून या कानून के बल वाले नियमों या आदेशों द्वारा लगाया जा सकता है। **(एम.आर. अप्पा राव[3]; कल्याण सिंह[1]).** कानूनी अधिकार के बिना कोई भी व्यक्ति परमादेश की मांग नहीं कर सकता। न्यायिक रूप से लागू करने योग्य अधिकार के साथ-साथ कानूनी रूप से संरक्षित अधिकार भी होना चाहिए, इससे पहले कि कोई व्यक्ति, जो कानूनी शिकायत से पीड़ित है, परमादेश मांग सके। किसी व्यक्ति को केवल तभी व्यथित कहा जा सकता है जब उसे किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कानूनी अधिकार से वंचित कर दिया जाता है जिसका कुछ करने का कानूनी कर्तव्य है या कुछ करने से बचना है। **(हेल्सबरीज़ लॉज़ ऑफ़ इंग्लैंड, चौथा संस्करण, खंड I, पैरा 122; सुभाष चंदर मारवाह[11]; जसभाई मोतीभाई देसाई[12];फेरिस:असाधारण कानूनी उपाय, पैरा 198; और मणि सुब्रत जैन[13])**. किसी प्राधिकारी को कुछ करने के लिए मजबूर करने के लिए परमादेश जारी किया जा सकता है, यह दिखाया जाना चाहिए कि क़ानून उस प्राधिकारी पर एक कानूनी कर्तव्य लगाता है, और पीड़ित पक्ष के पास क़ानून के तहत अपने प्रदर्शन को लागू करने का कानूनी अधिकार है। **(सुभाष चंदर मारवाह[11]; राय शिवेंद्र बहादुर (डॉ.)[7])** यदि दावे के लिए कोई वैधानिक आधार नहीं है, और क़ानून में दायित्व लगाने का कोई प्रावधान नहीं है, तो यह परमादेश की रिट जारी करने के लिए आधार प्रदान नहीं करेगा। **(ई. मर्क इंडिया[1] 4)**। कानून की शक्ति वाला कोई भी प्रावधान, जो याचिकाकर्ता को ऐसा कोई अधिकार प्रदान करता हो, हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है। इसलिए, अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह की गई इस दलील से सहमत होना हमारे लिए मुश्किल है कि विद्वान एकल न्यायाधीश ने ऐसी रिट जारी करने से इनकार करके गलती की है।

12. चूंकि दिनांक ०४-०९-२०१८ के विज्ञापन के खंड (1), (6), (19) और (21) पर दोनों पक्षों के विद्वान वकील द्वारा जोर दिया गया है, इसलिए इसकी सामग्री पर ध्यान देना आवश्यक है। हिन्दी में उपरोक्त खंड, जब अंग्रेजी में अनुवादित किए जाते हैं, तो इस प्रकार पढ़े जाते हैंः

"खंड (1):

उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन पत्र में ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज आरक्षण से संबंधित अपनी श्रेणी/उप-श्रेणी का उल्लेख करना होगा।आरक्षण हेतु दावा प्रस्तुत न करने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय, नैनीताल द्वारा विशेष अपील संख्या 79 सन् 2010 दिनांक 08.06.2010 ''राधा मित्तल बनाम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग '' एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19532/2010 की अगली कड़ी में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा।--आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार के पास आरक्षण से संबंधित प्रमाण पत्र होना चाहिए।

खंड (6):
आवेदन पत्र में की गई प्रविष्टियों में बदलाव का अनुरोध, जैसे किः आयोग के समक्ष आवेदन पत्र जमा करने के बाद पद का नाम, पात्रता, आरक्षण से संबंधित श्रेणी/उपश्रेणी, विषय, शाखा, आयु और परीक्षा केंद्र आदि स्वीकार नहीं किए जाएंगे।

खंड (19):
परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे प्रवेश के लिए सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं जो पूरी तरह से अस्थायी होगा, और पात्रता मानदंडों की पूर्ति पर निर्भर करेगा।केवल प्रवेश पत्र/साक्षात्कार का ज्ञापन जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि उनकी उम्मीदवारी अंततः आयोग द्वारा स्वीकार कर ली गई है।यदि, किसी भी स्तर पर, यह पाया जाता है कि उम्मीदवार पात्र नहीं था या उसका आवेदन पत्र रद्द कर दिया जाना चाहिए था या प्रारंभिक चरण में इसे अस्वीकार कर दिया जाना चाहिए था, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी और यदि वह अंतिम रूप से चयनित/अनुशंसित होता है, फिर भी उनके चयन की संस्तुति शासन से वापस ले ली जायेगी।

खंड (21):
यदि कोई उम्मीदवार अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र/उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।

13. दिनांक 04.09.2018 के विज्ञापन के खंड (1) के अनुसार, उम्मीदवारों को आरक्षण के लाभ का दावा करने के लिए अपनी श्रेणियों/उप-श्रेणियों को इंगित करना आवश्यक था। उक्त खंड में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि अभ्यर्थी आरक्षण के लिए कोई दावा नहीं करते हैं, तो उन्हें इस न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा 2010 की विशेष अपील संख्या 79 दिनांक 08-06-2010 और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित एसएलपी (सिविल) क्रमांक 19532 ऑफ 2010 के आदेश के परिणामस्वरूप आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने, अनुसूचित जाति का सदस्य होने के बावजूद, आवेदन पत्र के प्रासंगिक कॉलम "क्या वह आरक्षण के लाभ का दावा करना चाहता है" के जवाब में, विशेष रूप से नकारात्मक में संकेत दिया, यह दर्शाता है कि वह अनुसूचित जाति के सदस्यों को दिए गए आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहता था। ऐसी परिस्थितियों में, उसे "अनारक्षित" मानते हुए एक प्रवेश पत्र जारी किया गया था।

14. हालांकि, इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह सच है कि अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता ने इसके बाद आवेदन पत्र में सुधार की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था, विअभ्यावेदन के खंड (6) ने आयोग को आवेदन जमा करने के पश्चात आरक्षण से संबंधित श्रेणियों/उप-श्रेणियों जैसे आवेदन पत्र में प्रविष्टियों में परिवर्तन करने के लिए किसी भी अनुरोध पर विचार करने से लोक सेवा आयोग को अक्षम कर दिया। चूँकि आयोग विज्ञापन की शर्तों का सख्ती से पालन करने के लिए बाध्य है, और यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी आवेदकों के साथ समान व्यवहार किया जाए, इस आधार पर याचिकाकर्ता के आवेदन की अस्वीकृति को गलत नहीं माना जा सकता है।

15. यह सच है कि विज्ञापन दिनांक 04.09.2018 के खंड (21) में कहा गया है कि यदि कोई उम्मीदवार अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित शुल्क से कम शुल्क जमा करता है, तो उसका आवेदन पत्र रद्द किया जा सकता है।यह भी सच है कि, विज्ञापन के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शुल्क 100/- रुपये था, जबकि अनुसूचित जाति के सदस्यों सहित अन्य सभी आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए

निर्धारित शुल्क 60/- रुपये था।हालाँकि, हम याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता डॉ. हर्षवीर प्रकाश शर्मा की इस दलील से प्रभावित नहीं हैं कि चूँकि 60/- रुपये के शुल्क के साथ जमा किया गया उनका फॉर्म स्वीकार कर लिया गया था, इसलिए प्रतिवादी-आयोग को यह बहस करने से रोक दिया गया है कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने अनुसूचित जाति के सदस्य के रूप में आवेदन नहीं किया था।

16. ब्लैक लॉ डिक्शनरी "एस्टोपेल" को एक ऐसी रोक के रूप में परिभाषित करती है जो किसी को किसी दावे या अधिकार का दावा करने से रोकती है जो कि किसी ने पहले जो कहा या किया है या जो कानूनी रूप से सत्य के रूप में स्थापित किया गया है उसका खंडन करता है; एक बार जो मुद्दों पर दोबारा मुकदमेबाजी को रोकता है; एक सकारात्मक बचाव जिसमें सद्भावना, भ्रामक प्रतिनिधित्व पर निर्भरता और उस निर्भरता के परिणामस्वरूप स्थिति में चोट या हानिकारक परिवर्तन का आरोप लगाया गया है।ब्लैक लॉ डिक्शनरी न्यायसंगत रोक, या आचरण द्वारा रोक को एक रक्षात्मक सिद्धांत के रूप में परिभाषित करती है, जो एक पक्ष को दूसरे का अनुचित लाभ लेने से रोकता है, जब झूठी भाषा या आचरण के माध्यम से, रोके जाने वाले व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति को एक निश्चित तरीके से कार्य करने के लिए प्रेरित किया है, जिसके परिणामस्वरूप दूसरा व्यक्ति किसी तरह से घायल हो गया।यह सिद्धांत धोखाधड़ी के सिद्धांतों पर आधारित है।

17. **पी. रामनाथ अय्यरःलॉ लेक्सिकॉन** "एस्टोपेल" को एक प्रवेश के रूप में परिभाषित करता है, या कुछ ऐसा जिसे कानून एक प्रवेश के बराबर मानता है, इतनी उच्च और निर्णायक प्रकृति का कि जो कोई भी इससे प्रभावित होता है उसे इसका खंडन करने की अनुमति नहीं है।एस्टॉपेल किसी व्यक्ति के स्वयं के कृत्य से उत्पन्न होने वाले कार्रवाई के अधिकार में एक अवरोध या बाधा है; या जहां कानून द्वारा उसे अपने ही काम के खिलाफ बोलने से मना किया जाता है, उसके कार्य या स्वीकृति से, उसे आरोप लगाने या सच बोलने से रोका जा सकता है। व्यापक अर्थों में "एस्टोपेल" शब्द एक ऐसा अवरोध है जो किसी व्यक्ति को किसी ऐसे तथ्य की सच्चाई से इनकार करने से रोकता

है, जो कानून के विचार में न्यायिक या विधायी अधिकारियों के कार्यों और कार्यवाहियों द्वारा, या स्वयं पार्टी के कार्य द्वारा, या तो पारंपरिक लेखन द्वारा या अभ्यावेदन द्वारा, व्यक्त या निहित हो जाता है।एस्टोपेल एक न्यायसंगत राहत है और जहां यह उसके दूसरे सही दावे को धोखा देकर संचालित किया जाता है, तो उसे दूसरे को अपने अधिकारों से वंचित करने में मदद करना प्रभावी नहीं होगा।"रोक" का अर्थ है कि एक पक्ष को अपने स्वयं के कार्यों द्वारा दूसरे पक्ष के नुकसान के अधिकार का दावा करने से रोका जाता है जो इस तरह के आचरण पर भरोसा करने का हकदार था, और उसने तदनुसार कार्य किया है।एक सिद्धान्त जो यह प्रदान करता है कि एक व्यक्ति को उस व्यक्ति के पिछले आचरण, आरोप या इनकार के कारण किसी निश्चित तथ्य या तथ्यों की स्थिति को नकारने या आरोप लगाने से रोक दिया जाता है।एक सिद्धांत जो यह मानता है कि एक असंगत स्थिति, दृष्टिकोण या आचरण के पाठ्यक्रम को दूसरे को नुकसान या चोट के लिए नहीं अपनाया जा सकता है।जब एक व्यक्ति अपनी घोषणा, कार्य या चूक द्वारा जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को किसी बात को सच मुकदमा और उस विश्वास पर कार्य करने की अनुमति देता है, तो न तो उसे और न ही उसके प्रतिनिधि को उसके और ऐसे व्यक्ति या उसके प्रतिनिधि के बीच किसी मुकदमे या कार्यवाही में उस बात की सच्चाई से इनकार करने की अनुमति दी जाएगी।

18. आधुनिक समय में, बहिष्कार के सिद्धांत का विस्तार किया गया है ताकि व्यावहारिक रूप से किसी भी पक्ष द्वारा किसी भी कार्य या बयान को अपनाया जा सके जिसे उसे अस्वीकार करने की अनुमति देना अनुचित होगा। इस नियम को आधिकारिक रूप से इस प्रकार कहा गया हैः "जहाँ एक व्यक्ति अपने शब्दों या आचरण से जानबूझकर दूसरे को एक निश्चित स्थिति के अस्तित्व पर विश्वास करने के लिए प्रेरित करता है, और उसे उस विश्वास पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है ताकि वह अपनी पिछली स्थिति को बदल सके, तो पहले वाले को बाद वाले के विरुद्ध एक अलग स्थिति को टालने से रोका जाता है जो एक ही समय में मौजूद थी।और किसी व्यक्ति का वास्तविक इरादा जो भी हो, उसे जानबूझकर कार्य करने वाला माना जाता है "यदि वह

ऐसा आचरण करता है कि एक उचित व्यक्ति प्रतिनिधित्व को सच मान लेगा और विश्वास करेगा कि इसका मतलब यह है कि उसे इस पर कार्य करना चाहिए। **(फ्रीमैन बनाम कुक[15]; पिकार्ड बनाम सीयर्स "; फिप्सन ऑन एविडेंस (चौदहवां संस्करण); टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड[17])**

19. आचरण द्वारा रोक के मुद्दे को केवल सटीक और स्पष्ट प्रतिनिधित्व होने की स्थिति में ही उपलब्ध माना जा सकता है, और उस स्कोर पर एक और सवाल उठता है कि क्या कोई स्पष्ट आश्वासन था जो आश्वासन देने वाले को अपनी स्थिति या अवस्था बदलने के लिए प्रेरित कर रहा था। जहाँ आचरण लापरवाहीपूर्ण है या इसमें पूरी तरह से चूक शामिल है, वहाँ गुमराह व्यक्ति के लिए एक कर्तव्य होना चाहिए।**(मर्केंटाइल बैंक बनाम सेंट्रल बैंक [18]; नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक "; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड[17]; फिप्सन ऑन एविडेंस (चौदहवां संस्करण); मूरगेट मर्केंटाइल कंपनी लिमिटेड [20])।**

20. रोक लगाने वाली पार्टी को उसके नुकसान के लिए कार्य करने के लिए प्रेरित किया गया होगा। जब तक धारणा का पालन किया जाता है, वह पक्ष जिसने अपने विश्वास पर स्थिति को बदल दिया है, वह शिकायत नहीं कर सकता है।**(टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड[17]; ग्रुंड्ट[21])**। यह मात्र तभी होता है जब अभ्यावेदन करने वाला अपने अभ्यावेदन में निहित धारणा को अस्वीकार करना चाहता है कि एक अवरोध उत्पन्न होता है, और नुकसान के प्रश्न पर विचार किया जाता है, तदनुसार, उस स्थिति के आलोक में जो अभ्यावेदन करने वाले को अभ्यावेदन की सच्चाई को अस्वीकार करने की अनुमति दी गई थी।**(ग्रंड्ट [21]; टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी Ltd.[17]; स्पेंसर बोवर और टर्नरः प्रतिनिधित्व द्वारा रोक तृतीय संस्करण।; सेंट्रल न्यूबरी कार ऑक्शन लिमिटेड[22])।** एस्टोपेल वाद हेतुक नहीं है। यह साक्ष्य का नियम है।**(ऑल इंडिया पावर इंजीनियर फेडरेशन[23]; कृष्ण बहादुर[24]).** रोक लगाने में अधिकार को परित्याग करना या आत्मसमर्पण करने का वास्तविक इरादा मायने नहीं रखता है। आवश्यक शर्त यह है कि एक पक्ष के आचरण से दूसरे पक्ष को नुकसान हो। एक

बहिष्करण का परिणाम हो सकता है, हालांकि बहिष्कृत पार्टी का कोई मौजूदा अधिकार खोने का इरादा नहीं था। **(प्रोवाश चंद्र दलुई [25])।**

21. यह विवादित नहीं है कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता अनुसूचित जाति का सदस्य है। ऐसे में, उन्हें केवल 60/- रुपये का आवेदन शुल्क देना होगा। आरक्षित श्रेणी से संबंधित होने के बावजूद, यह उन्हें तय करना था कि आरक्षण के लाभ का दावा करना है या नहीं और चूंकि उन्होंने अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कहा था कि वह इस तरह के लाभ का दावा नहीं करना चाहते हैं, इसलिए उन्हें "अनारक्षित" माना गया। इसका मतलब यह नहीं है कि उसे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित 100/- रुपये का आवेदन शुल्क भी देना होगा चूंकि वह अनुसूचित जाति से है, और अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शुल्क केवल 60/- रुपये था। इसलिए, लोक सेवा आयोग द्वारा 60/- रुपये के निर्धारित शुल्क के साथ उनके आवेदन पत्र को स्वीकार करना उचित था।

22. जैसा कि अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र के प्रासंगिक कॉलम में विशेष रूप से नकारात्मक में संकेत दिया था, जिसमें उसे यह बताना आवश्यक था कि क्या वह आरक्षण के लाभ का दावा करना चाहता है, केवल इस तथ्य से कि उसका आवेदन 60/- रुपये के शुल्क के साथ स्वीकार कर लिया गया था, यह नहीं माना जा सकता है कि लोक सेवा आयोग ने अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को अनुसूचित जाति श्रेणी के तहत आवेदन किया है, और आरक्षण के लाभ का दावा करने का हकदार माना है। यह मात्र तभी है जब एक पक्ष ने किसी ऐसी चीज को स्वीकार किया है, जिससे दूसरा प्रभावित होता है, तो पहले वाले को इसका खंडन करने की अनुमति नहीं है। वास्तव में, कानून एक व्यक्ति को अपने स्वयं के कार्य या कार्य के विरुद्ध बोलने से मना करता है जिसने दूसरे को प्रभावित किया है।वर्तमान मामले में, यह अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता है, जिसने नकारात्मक में प्रासंगिक कॉलम दाखिल करके स्वीकार किया है कि वह आरक्षण का लाभ नहीं लेना चाहता था, हालांकि वह आरक्षित श्रेणी से संबंधित था। आयोग की ओर से न तो कोई स्वीकारोक्ति की गई है

और न ही उनकी ओर से ऐसा कोई कार्य या कृत्य हुआ है जिससे अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा हो।

23. यह अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता है, जिसने एक ओर जहां 60/- रुपये की कम फीस का भुगतान किया है (यानी आरक्षित श्रेणी पर लागू कम फीस), वहीं दूसरी ओर, उसने आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करने का विकल्प चुना है।उपरोक्त दोनों कार्य अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता के हैं न कि प्रतिवादी-आयोग के।केवल यह तथ्य कि आयोग को अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता का आवेदन प्राप्त हुआ था, 60/- रुपये के कम शुल्क का यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि उन्होंने अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता के आवेदन को अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षित पद के लिए किया गया माना है, जब अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में स्पष्ट रूप से कहा है कि वह आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहता है।

24. **नीतू हर्ष**[1] मामले में, जिस पर अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता की ओर से भरोसा किया गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ ने कहा:

> "..... यह भी एक स्वीकृत तथ्य है कि राजस्थान न्यायिक सेवा परीक्षा, 2016 में उपस्थित होने के लिए ऑनलाइन आवेदन में, विकलांग व्यक्ति (अलग तरह से सक्षम) के लिए कॉलम नंबर 3 (i) के सामने गलती से, याचिकाकर्ता ने "नहीं" का उल्लेख किया था लेकिन दिनांक 15.11.2016 को मुख्य परीक्षा के अंतिम परिणाम की घोषणा के तुरंत बाद, याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 28.11.2016 को एक अभ्यावेदन (34 में से 32) [सीडब्ल्यू 692/2017] प्रस्तुत किया गया, जिसमें उसके द्वारा 'विकलांग व्यक्ति' की श्रेणी के तहत राजस्थान न्यायिक सेवा प्रतियोगी परीक्षा, 2016 में उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने की प्रार्थना की गई और उपरोक्त सभी तथ्य उत्तरदाता संख्या १ और २ को बताए गए थे और उसकी उम्मीदवारी को विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में माना जाए क्योंकि उसकी विकलांगता 80% है।----माना जाता है कि, परिणाम घोषित होने के बाद, नियुक्ति आदेश जारी होने से बहुत पहले 28.11.2016 को अभ्यावेदन दायर किया गया था और प्रस्तुत किया गया था कि विकलांग श्रेणी के लिए आरक्षित रखे गए दो पदों में से एक खाली पद उपलब्ध है, जिस पर उसकी उम्मीदवारी को शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार की श्रेणी में मानते हुए उसकी उम्मीदवारी पर विचार किया जा सकता है।यह सच है कि प्रतिवादी की कोई गलती नहीं है क्योंकि याचिकाकर्ता को अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दी गई जानकारी के अनुसार सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार के रूप में प्रतियोगी परीक्षा में बैठने की

अनुमति दी गई थी।हमारी राय में, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवार एक वर्ग से अलग है, इसलिए, अधिनियम 1995 के अधिनियमन के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, परीक्षा में उपस्थित होने के बाद भी, उसके द्वारा की गई गलती को सुधारने के लिए प्रार्थना करते समय, उत्तरदाताओं का दायित्व था कि वे याचिकाकर्ता की उसकी उम्मीदवारी को विकलांग व्यक्ति की श्रेणी में मानने की प्रार्थना स्वीकार करें क्योंकि उसके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की तिथि पर उनके पास उक्त श्रेणी का एक रिक्त पद उपलब्ध था।अधिनियम 1995 की धारा 36 के तहत, नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रखी गई रिक्ति को पहले विकलांगता वाले उम्मीदवारों से भरने का प्रयास किया जाना चाहिए और ऐसे उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में, श्रेणी पद को अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जाना चाहिए।इस मामले में, उत्तरदाताओं द्वारा कहीं भी यह दलील नहीं दी गई है कि जो पद खाली रह गया था उसे पहले आगे बढ़ा दिया गया था, इसलिए, वे विकलांग व्यक्ति के अलावा अन्य उम्मीदवार से उक्त रिक्ति को भरने के लिए स्वतंत्र थे।नियुक्ति के लिए विचार के समय, यह उनकी जानकारी में था कि विकलांग याचिकाकर्ता उपलब्ध है, जिस पर नियुक्ति के लिए विचार किया जा सकता है, लेकिन अधिनियम की धारा 36 की भावना पर विचार किए बिना, याचिकाकर्ता के अभ्यावेदन को "विचार और अस्वीकार" कहकर खारिज कर दिया गया था।उपरोक्त चर्चा के आधार पर, 1995 के अधिनियम को लागू करने के लिए विधायिका के इरादे पर विचार करने के लिए, हमारा विचार है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई गलती को सुधारने के लिए प्रतिवादी द्वारा क्षमा के सिद्धांत को लागू करने की आवश्यकता थी क्योंकि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था कि "कमजोर कभी क्षमा नहीं करते हैं,क्षमा का श्रेय बलवान को दिया जाता है'' अत: सशक्त उत्तरदाताओं से यह अपेक्षा की जाती थी की रिक्ति, जिसे विकलांग अभ्यर्थी के लिए आरक्षित रखा गया है, की उपलब्धता की स्थिति में ऐसे विकलांग उम्मीदवार, जिसे हम भारत के संविधान के अनुसार समाज के कमजोर वर्ग के रूप में मान रहे हैं, के कल्याण के लिए एक पवित्र निर्णय लिया जाना चाहिए था।

उपरोक्त चर्चा के मद्देनजर, हम मानते हैं कि याचिकाकर्ता की शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार की श्रेणी के तहत उसकी उम्मीदवारी पर विचार करने की प्रार्थना को अस्वीकार करना 1995 के अधिनियम की भावना के अनुरूप नहीं है ....." (जोर दिया गया)

25. **नीतू हर्ष**' मामले में याचिकाकर्ता, एक शारीरिक रूप से विकलांग आवेदक, ने अपने आवेदन पत्र के संबंधित कॉलम में यह पूछा था कि क्या वह शारीरिक विकलांगता से पीड़ित है, इसका उत्तर 'न' में दिया गया था। राजस्थान उच्च न्यायालय की एक

खंडपीठ ने कहा कि, विकलांग व्यक्ति अधिनियम, 1995 (इसके बाद "1995 अधिनियम" के रूप में संदर्भित) के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उत्तरदाताओं का दायित्व था कि वे याचिकाकर्ता को विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में मानें, क्योंकि उनके अभ्यावेदन पर निर्णय लेने की तिथि पर, शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में एक रिक्त पद भरने के लिए उपलब्ध था।1995 अधिनियम की धारा 36 नियोक्ता पर यह कर्तव्य डालती है कि वह शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के पक्ष में आरक्षित रिक्ति को पहले ऐसी विकलांगता से पीड़ित लोगों से भरने का प्रयास करे; और ऐसी श्रेणी से उम्मीदवार की अनुपलब्धता की स्थिति में ही, पद को अगले भर्ती वर्ष में आगे बढ़ाया जा सकता है।1995 के अधिनियम के अनुसार, उत्तरदाताओं से अपेक्षा की गई थी कि शारीरिक रूप से अक्षम लोगों के पक्ष में आरक्षित पद की रिक्ति की स्थिति में, उक्त पद को केवल उक्त श्रेणी के उम्मीदवार से भरा जाए।

26. **नीतू हर्ष**[1] मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ की उपरोक्त टिप्पणियाँ 1995 के अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों के आलोक में की गई थीं। उक्त मामले में, पद को भरने के लिए कोई अन्य शारीरिक रूप से अक्षम उम्मीदवार उपलब्ध नहीं थे। याचिकाकर्ता को उक्त पद पर नियुक्त करने में विफलता के परिणामस्वरूप शारीरिक रूप से विकलांगों के पक्ष में आरक्षित एक रिक्ति खाली रह जाती।नीतू हर्ष[1] मामले के विपरीत, ऐसा कोई वैधानिक प्रावधान हमारे संज्ञान में नहीं लाया गया है जो प्रतिवादी आयोग को अनुसूचित जाति के पक्ष में आरक्षित पदों पर साक्षात्कार के लिए अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता को बुलाने के लिए बाध्य करता हो, भले ही उसने घोषणा की हो कि वह आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करना चाहता है। **नीतू हर्ष**[1] मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ की मत पर अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता द्वारा रखा गया अवलम्ब इसलिए गलत है।

27. अन्यथा भी, उच्च न्यायालय के निर्णय में मात्र उस राज्य या क्षेत्रों में एक बाध्यकारी मिसाल का बल होता है जिस पर न्यायालय का क्षेत्राधिकार होता है। अन्य राज्यों में या उस उच्च न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र के बाहर, इसका अधिक से

अधिक, प्रेरक प्रभाव हो सकता है। जहां तक अन्य उच्च न्यायालयों का संबंध है, ''स्टेयर डिसिसिस'' के सिद्धांत को इतना नहीं बढ़ाया जा सकता कि एक उच्च न्यायालय के निर्णयों को एक बाध्यकारी मिसाल का दर्जा दिया जा सके। **(जेफ्री मैनर्स एंड कंपनी लिमिटेड [26]; थाना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड[27]; कंसोलिडेटेड न्यूमेटिक टूल कंपनी[28])**।यह सिद्धांत मात्र एक ही उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों पर लागू होता है।अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों के अनुपात को बाध्यकारी मिसाल की स्थिति तक नहीं बढ़ाया जा सकता है न ही उन निर्णयों के अनुपात निर्णय को ''स्टेयर डिसिसिस'' के सिद्धांत को लागू करके कायम रखा जा सकता है।**(वल्लियामा चंपका पिल्लई[29]; थाना विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड[27])**। न्यायिक मर्यादा, औचित्य और अनुशासन की आवश्यकता है कि उच्च न्यायालय को, विशेष रूप से अपने विपरीत दृष्टिकोण या असहमति की स्थिति में, अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों पर चर्चा करनी चाहिए और अपने विपरीत दृष्टिकोण के लिए अपने स्वयं के कारणों को दर्ज करना चाहिए।एक उच्च न्यायालय को अन्य उच्च न्यायालयों द्वारा अपनाए गए दृष्टिकोण से असहमत होने का अधिकार है, लेकिन पूरी निष्पक्षता से, उसे कारणों के साथ अपनी असहमति दर्ज करनी चाहिए। अन्य उच्च न्यायालयों के निर्णयों का प्रेरक महत्व है, इस पर उच्च न्यायालय को ध्यान देना चाहिए और केवल अपने स्वयं के कारणों को दर्ज करके ही असहमति व्यक्त करनी चाहिए। **(प्रदीप जे. मेहता[30])**।

28. राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा **नीतू हर्ष**[1] मामले में घोषित कानून को वर्तमान मामले में लागू करने से लोक सेवा आयोग विज्ञापन में स्वयं के निर्देशों का उल्लंघन करेगा। अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ता की ओर से आग्रह किए गए तर्क को स्वीकार करने के लिए, इस न्यायालय को आयोग को अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को रियायत देने का निर्देश देने की आवश्यकता होगी जो किसी अन्य उम्मीदवार को नहीं दी गई है। अधिसूचना के खंड (1) में प्रावधान है कि आरक्षण का दावा नहीं करने की स्थिति में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जायेगा.याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में विशेष रूप से कहा है कि वह आरक्षण के

लाभ का दावा नहीं करना चाहते थे। अधिसूचना के खंड (6) में कहा गया है कि आयोग को प्रस्तुत किए जाने के पश्चात आवेदन पत्र में प्रविष्टियों को बदलने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।अपीलकर्ता-रिट याचिकाकर्ता ने, स्वीकार करते हुए, अपना आवेदन पत्र आयोग को प्रस्तुत किया था; और एडमिट कार्ड प्राप्त होने के बाद ही, जिसमे उसे अनारक्षित दिखाया गया था, उसने आवेदन पत्र में उसके द्वारा की गई प्रविष्टियों में बदलाव की मांग करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया था।विज्ञापन में उपरोक्त खंडों के आलोक में, हमें **नीतू हर्ष**[1] में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा व्यक्त की गई मत से सहमत होने या अपीलकर्ता-लिखित याचिकाकर्ता को आरक्षण का लाभ देने में अपनी असमर्थता व्यक्त करनी चाहिए, क्योंकि इसके लिए इस न्यायालय को उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को अपने स्वयं के निर्देशों के विपरीत कार्य करने का निर्देश देने के लिए एक परमादेश जारी करने की आवश्यकता होगी। संबंधित अधिकारियों के लिए कानून के विपरीत कार्य करने का परमादेश अस्वीकार्य है।

29. **यामिनी जोशी**[3] में, इस न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने कहाः

> "..... हमने अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत एकमात्र तर्क पर विचार किया है। वे सभी उम्मीदवार, जो आरक्षण के माध्यम से विचार किए जाने के इच्छुक थे, उन्हें कॉलम नंबर 12 पर जवाब देना आवश्यक था।कॉलम नं. 12 अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्ग श्रेणियों, रक्षा कार्मिकों, भूतपूर्व सैनिकों, खिलाड़ियों, उत्तरांचल राज्य में पहले से कार्यरत सरकारी कर्मचारियों, उत्तरांचल महिलाओं, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षण की परिकल्पना की गई, चाहे वे कम दृष्टि वाले हों, श्रवण बाधित हों या चलने-फिरने में अक्षम हों। **प्रत्येक उम्मीदवार, जो उपरोक्त आरक्षित श्रेणियों में से किसी के लिए विचार किए जाने का इच्छुक था, ओएमआर शीट के कॉलम नंबर 12 पर प्रतिक्रिया देने के लिए उत्तरदायी था, जिसमें उस विशेष आरक्षण को दर्शाया गया था जिसका उम्मीदवार दावा कर रहा था।निर्विवाद रूप से, अपीलकर्ता ने उत्तरांचल महिला के रूप में आरक्षण का दावा करने के लिए कॉलम नंबर 12 नहीं भरा।इस प्रकार, विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 05-05-2010 को आक्षेपित आदेश पारित करके प्रतिवादी को उत्तरांचल महिलाओं की आरक्षित श्रेणी के विरुद्ध अपीलकर्ता पर विचार करने का निर्देश जारी करके अपीलकर्ता के दावे को अस्वीकार कर दिया।हमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए तत्काल निर्णय में कोई अशक्ति नहीं मिली।यह स्पष्ट है कि अपीलकर्ता ने कॉलम संख्या 12 नहीं भरा।उत्तरांचल**

महिला के रूप में आरक्षण का दावा करने के लिए कॉलम नंबर 12 को भरने में असफल होने के बावजूद, भले ही उन्हें इस तरह के आरक्षण की मांग करने वाली अन्य उत्तरांचल महिलाओं की तुलना में अधिक अंक दिए गए हों, उनके दावे का मूल्यांकन उत्तरांचल महिला की आरक्षित श्रेणी से नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसने इसके लिए कभी आवेदन नहीं किया था....."

(जोर दिया गया)

30. **यामिनी जोशी**[3] मामले में, अन्य लोगों के अलावा, उत्तरांचल की महिलाओं के लिए आरक्षण प्रदान किया गया था। आवेदन पत्र के कॉलम नंबर 12 में उस विशेष आरक्षण को दर्शाया गया है जिसका उम्मीदवार दावा कर रहा था।चूंकि याचिकाकर्ता ने कॉलम नंबर 12 नहीं भरा था, इसलिए उसे उत्तरांचल की महिला के रूप में आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया था। इस संदर्भ में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने पाया कि आवेदक, कॉलम नंबर 12 को भरने में विफल रही है, इसलिए वह इस बात पर जोर नहीं दे सकती है कि उसके दावे का मूल्यांकन आरक्षित श्रेणी के लिए किया जाना चाहिए, क्योंकि उसने कभी भी इसके लिए आवेदन नहीं किया था। इसी तरह, वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने आरक्षण का दावा करने से इनकार कर दिया है, अब वह पलटकर यह दलील नहीं दे सकता है कि आवेदन पत्र में उसके विशिष्ट दावे के बावजूद, उसे आरक्षण का लाभ दिया जाना चाहिए। **नीतू हर्ष**[1] मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खंडपीठ का फैसला, जिसका केवल प्रेरक मूल्य है, के विपरीत, **यामिनी जोशी**[3] मामले में इस न्यायालय की खंडपीठ का फैसला हमें बाध्य करता है।

31. समन्वय पीठ के फैसले की अनदेखी करना न्यायिक अनुचितता है। न्यायिक समिति की मांग है कि जिस बाध्यकारी निर्णय की ओर उनका ध्यान आकर्षित किया गया था, उसे किसी न्यायाधीश द्वारा न तो उपेक्षित किया जाना चाहिए और न ही नजरअंदाज किया जाना चाहिए। (**यादव इंजीनियर एवं ठेकेदार**[31]**; थाना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड**[27]**)**। बाध्यकारी पूर्ववर्ती का सिद्धांत केवल एक ही उच्च न्यायालय की विभिन्न पीठों पर लागू होता है। **(वल्लियामा चंपक पिल्लई**[2]**)**। यदि कानून में किसी भी अन्य चीज की तुलना में एक चीज अधिक आवश्यक है, तो वह है निश्चितता की गुणवत्ता। यदि उच्च न्यायालय में समन्वित क्षेत्राधिकार के न्यायाधीश

एक-दूसरे के निर्णयों को खारिज करना शुरू कर दें तो यह गुणवत्ता गायब हो जाएगी।**(महादेवलाल कनोडिया[3]2; थाना इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड[27])।** जैसा कि **यामिनी जोशी[3]** का निर्णय हमें बाध्य करता है, हमें **नीतू हर्ष[1]** मामले में राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ द्वारा लिए गए विपरीत दृष्टिकोण से सहमत होने में अपनी असमर्थता को सम्मानपूर्वक व्यक्त करना चाहिए।

32. **नीतू हर्ष[1]** में, राजस्थान उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने **सीमा कुमारी शर्मा[2]** में निर्णय का उल्लेख किया था, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने कहा थाः

> "……चयन मैट्रिक या समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंकों के प्रतिशत के आधार पर 100 अंकों का था। ग्रामीण क्षेत्रों के उम्मीदवारों के लिए 20 अंक और पिछड़े पंचायत के उम्मीदवारों के लिए 10 अंक आवंटित किए गए थे।**इसी तरह, आईआरडीपी परिवारों से संबंधित उम्मीदवारों के लिए 10 अंक आवंटित किए गए थे।हालांकि अपीलकर्ता ने आईआरडीपी परिवार से होने का दावा किया, लेकिन अधिकारियों ने उसके दावे पर विचार नहीं किया और परिणामस्वरूप मानदंड के तहत आवश्यक 10 अंक नहीं दिए।जब अपीलकर्ता ने रिट याचिका दायर की, तो उच्च न्यायालय ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अपीलकर्ता ने आवेदन के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया था और इसलिए, वह उपरोक्त स्थिति की हकदार नहीं है।जब हमने अपीलकर्ता को अभिलेख प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, तो उसने प्रमाणपत्र को अभिलेख का एक हिस्सा बना दिया।दुर्भाग्य से, इसमें जारी करने की तिथि नहीं है; लेकिन हम पाते हैं कि उन्हें आई. आर. डी. पी. परिवार का क्रम संख्या दी गई है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि क्रम में सभी उम्मीदवारों को क्रमांक दिए गए हैं, हमारा विचार है कि आवेदन के साथ प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में उसकी विफलता उसे 10 अंकों के पुरस्कार के विचार के लिए स्थिति का दावा करने से वंचित नहीं करती है। इस न्यायालय द्वारा दिए गए अंतरिम निर्देश के अनुसार, अपीलकर्ता पहले ही आयोजित परीक्षाओं के लिए उपस्थित हो चुकी है लेकिन उसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है।**
>
> इसलिए, अपीलों की अनुमति दी जाती है; न्यायाधिकरण का आदेश अपास्त दिया जाता है।परिणाम घोषित करने का निर्देश दिया जाएगा और यदि उसका चयन हो जाता है तो उसकी नियुक्ति के मामले पर नियमानुसार विचार किया जाएगा।कोई लागत नहीं। "
>
> (जोर दिया गया)

33. उपरोक्त निर्देश भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी किए गए थे। संविधान ने, अनुच्छेद

142 द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय को ऐसे आदेश देने का अधिकार दिया है जो "उसके समक्ष लंबित किसी मामले या मामले में पूर्ण न्याय करने के लिए" आवश्यक हो सकते हैं, जो अधिकार उच्च न्यायालय को प्राप्त नहीं है।रिट कार्यवाही में उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार उन सीमाओं से घिरा होता है जिनका उल्लंघन न्यायाधीश से न्यायाधीश की अलग-अलग न्याय की इच्छा या व्यक्तिपरक भावना से नहीं किया जा सकता है।**(सुरिंदर कुमार[33]).** अनुच्छेद 142 के तहत जो शक्ति सर्वोच्च न्यायालय को उपलब्ध है वह उच्च न्यायालयों को उपलब्ध नहीं है। **(सुकामणि दास [34]).**

34. भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को प्रदत्त शक्ति, भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रदत्त संवैधानिक क्षेत्राधिकार के बराबर नहीं है। **(जौहरी माल[35]; एच.पी. राज्य बनाम मेडिकल कॉलेज के एक छात्र के माता-पिता[36] और आसिफ हमीद[37]; जौहरी माल[35]; सी.के. राजन[38]; बी.सी. चतुर्वेदी[39])।** संविधान के अनुच्छेद 142 (1) के तहत सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक रूप से प्रदत्त असाधारण क्षेत्राधिकार का प्रयोग, अनुच्छेद 226 के दायरे पर कोई मार्गदर्शन नहीं हो सकता है।(**नरेश कुमार बाली[1]; महेंद्र पाल[11]).** चूंकि भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को पूर्ण न्याय करने की जो शक्ति प्रदान की गई है, वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग करने के लिए उपलब्ध नहीं है, सीमा कुमारी शर्मा मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी किए गए निर्देश के समान, उच्च न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता है, खासकर तब जब यह अधिसूचना में निर्धारित स्पष्ट शर्तों के विपरीत हो।

35. याचिकाकर्ता द्वारा अधिसूचना (विज्ञापन) के खंड (19) पर यह तर्क देना कि केवल प्रवेश पत्र जारी करना निर्णायक नहीं है, गलत है। खंड (19) में कहा गया है कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी पात्रता मानदंडों को पूरा करते हैं और केवल प्रवेश पत्र/साक्षात्कार का ज्ञापन जारी करने का मतलब यह नहीं है कि आयोग द्वारा उम्मीदवारी को अंततः स्वीकार कर लिया गया है।विज्ञापन के खंड (19) के संदर्भ में उम्मीदवार पर पात्रता मानदंडों को पूरा करने

का दायित्व है और ऐसे मामलों में भी जहां पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करने वाले उम्मीदवार को गलती से प्रवेश पत्र जारी किया गया है, खंड (19) यह स्पष्ट करता है कि प्रवेश पत्र जारी करने का मतलब यह नहीं होगा कि आयोग द्वारा उम्मीदवारी स्वीकार कर ली गई है।वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने अपने आवेदन पत्र में विशेष रूप से यह कहते हुए आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करने का विकल्प चुना है।आयोग द्वारा उन्हें अनारक्षित उम्मीदवार मानते हुए जारी किया गया प्रवेश पत्र पूरी तरह से अपीलकर्ता रिट याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में कही गई बातों के अनुरूप है।इसलिए, खंड (19) का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

36. **नीतू हर्ष**[1] में प्रतिपादित क्षमा का सिद्धांत भी हमें आकर्षित नहीं करता। भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, यह उच्च न्यायालय का काम नहीं है कि वह ऐसी शर्तें निर्धारित करे, जिनकी पूर्ति से उम्मीदवार चयन प्रक्रिया में भाग लेने में सक्षम हो सके, क्योंकि भर्ती के लिए शर्तों को पूरा करना लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित किया जाना आवश्यक है और किया गया है। चूंकि अपीलार्थी-लिखित याचिकाकर्ता ने आयोग को अपने द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में आरक्षण के लाभ का दावा नहीं करने का विकल्प चुना है, इसलिए उसे दिनांकित विज्ञापन के खंड (1) और (6) में निर्धारित विशिष्ट शर्तों के विपरीत, आवेदन पत्र में सुधार करने की अनुमति देने के लिए इस न्यायालय से आयोग को एक परमादेश जारी करने की आवश्यकता होगी, ताकि विज्ञापन में निर्धारित शर्तों के बावजूद आवेदन को सही करने की अनुमति दी जा सके।एक उच्च न्यायालय को ऐसा नहीं करना चाहिए।

37. अंतर-न्यायालय अपील में हस्तक्षेप तभी उचित है जब अपील के तहत आदेश पेटेंट अवैधता से ग्रस्त हो। हमें अपील के तहत आदेश में ऐसी कोई खामी नहीं मिली। अपील विफल हो जाती है और तदनुसार खारिज कर दी जाती है। कोई लागत नहीं।

(N.S. धनिक, जे.) **(रमेश रंगनाथन, C.J.)**

03.04.2019 **03.04.2019**

राहुल